मूल हिंदी

भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3195

21 दिसंबर, 2023 को उत्तर के लिए

क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट प्रणाली

3195. श्री रमेश चन्द्र कौशिक:

डॉ. सत्यपाल सिंह:

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने दिल्ली से पानीपत तक क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट प्रणाली (आरआरटीएस) परियोजना को पूरा करने की मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या मेट्रो रेल की सीधी कनेक्टिविटी और क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट प्रणाली (आरआरटीएस) के दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ गलियारे का और विस्तार करने की भारी मांग है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री कौशल किशोर)

(क) और (ख): जी नहीं। दिल्ली-पानीपत रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) कॉरिडोर के लिए हरियाणा सरकार की मंजूरी और वित्तीय प्रतिबद्धता के साथ विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) प्राप्त हो गई है। हालाँकि, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) ने दिल्ली-पानीपत आरआरटीएस कॉरिडोर की डीपीआर को मंजूरी नहीं दी है।

(ग) से (घ): जी हाँ। इस मंत्रालय को दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर तक विस्तारित करने का संदर्भ प्राप्त हुआ था। 2017 के मेट्रो रेल नीति प्रावधानों के अनुसार संबंधित राज्य सरकार (सरकारें) आरआरटीएस परियोजनाओं सहित शहरी परिवहन इन्फ्रास्ट्रक्चर को शुरू करने, विकसित करने और वित्त पोषित करने के लिए जिम्मेदार हैं और केंद्र सरकार को जब भी संबंधित सरकार (सरकारों) से कोई प्रस्ताव प्राप्त होता है तो प्रस्ताव की व्यवहार्यता, आवश्यकता और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर शहरी रेल आधारित प्रणाली के लिए वित्तीय सहायता पर विचार करती है। तदनुसार, इस मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश सरकार से मेरठ-मुजफ्फरनगर कॉरिडोर पर वैकल्पिक विश्लेषण के साथ विस्तृत यातायात सर्वेक्षण करने के लिए कहा था और इस विस्तृत यातायात अध्ययन रिपोर्ट के नतीजे के आधार पर, उपयुक्त परिवहन प्रणालियों के लिए एक डीपीआर तैयार करने को भी कहा गया था। अब तक दिल्ली-गाजियाबाद मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर के विस्तार के लिए मंत्रालय को कोई डीपीआर प्राप्त नहीं हुई है।

*****